



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2019/चैत्र 11, 1941

No. 107]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2019/CHAITRA 11, 1941

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

सं.वाई-18020/9/2017-आईआईआईसी/सीएपी.—आंकड़ों के प्रसारण की आवश्यकता तथा इसमें छुपी संभावनाओं को देखते हुए सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने सांख्यिकीय आंकड़ा प्रसारण प्रणाली के सरलीकरण के उद्देश्य से मई, 1999 में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी। समय बीतने के साथ-साथ तथा प्रौद्योगिकीय प्रगति के कारण आंकड़ा प्रसारण की विधियों में काफी परिवर्तन हुआ है। अतः विद्यमान दिशा-निर्देशों में संशोधन की आवश्यकता है। इसके अलावा, मार्च 2012 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित "राष्ट्रीय डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (एनडीएसएपी)" के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के डाटा सेटों को 'साझा किए जाने योग्य आंकड़ा' तथा 'साझा न किए जाने योग्य आंकड़ा' के रूप में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित है तथा प्रतिबंधित पहुंच के अंतर्गत आंकड़ों संबंधी मूल्य नीति तैयार करनी होती है। तदनुसार, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा अन्य सांख्यिकीय एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए साझा करने योग्य तथा साझा नहीं करने योग्य आंकड़ों को परिभाषित करने और इसके प्रसारण के लिए नियम एवं शर्तें विनिर्दिष्ट करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़ा प्रसारण संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचित किए जा रहे हैं।

अनुसूची

सांख्यिकीय आंकड़ा प्रसारण के लिए दिशानिर्देश (जीएसडीडी)

(एनडीएसएपी, 2012 के अनुसार)

1. पृष्ठभूमि

सरकारी सांख्यिकी निर्णय लेने तथा नीति अंत-क्षेप में प्रमुख भूमिका निभाती है और सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान संचालन के लिए सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है। सरकारी सांख्यिकी को तैयार करने वालों के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान तथा सहयोग की संस्कृति से दोहरीकरण तथा अवांछनीयता से बचाव के कारण न केवल संसाधनों की बचत होती है, बल्कि इसमें नए ज्ञान संबंधी संपदा के सृजन की भी काफी संभावनाएं होती हैं। आंकड़ों के प्रसारण की आवश्यकता तथा इसमें छुपी संभावनाओं को देखते हुए सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के सरकारी आंकड़ा प्रसारण प्रणाली के सरलीकरण के उद्देश्य से मई, 1999 में सरकारी आंकड़ों के प्रसारण के संबंध में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी। समय बीतने के साथ-साथ तथा प्रौद्योगिकीय प्रगति के कारण आंकड़ा प्रसारण की विधियों में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। अतः विद्यमान दिशा-निर्देशों में संशोधन की आवश्यकता है। इसके अलावा, मार्च 2012 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने समस्त भारत में व्यापक क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से मशीन पठनीय रूप में भारत सरकार के स्वामित्व वाले साझा किए जाने योग्य आंकड़ों (इसकी प्रयोग सूचना सहित) तक पहुँच को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (एनडीएसएपी)" प्रतिपादित की थी। इसकी अनुपालना में, सार्वजनिक प्रयोग के लिए अक्टूबर 2012 में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के डाटासेटों, दस्तावेजों, सेवाओं, उपकरणों तथा एप्लीकेशनों की एकीकृत संचयिका ओपन गवर्नमेंट आंकड़ा (ओजीडी) प्लेटफॉर्म (www.data.gov.in) की शुरुआत की गई थी। एनडीएसएपी के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों द्वारा भू-स्थानिक तथा गैर-स्थानिक दोनों ही स्तर पर तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के डाटा सेटों को 'साझा किए जाने योग्य आंकड़ा' तथा 'साझा न किए जाने योग्य आंकड़ा' के रूप में वर्गीकृत किया जाना अपेक्षित है तथा प्रतिबंधित पहुँच के अंतर्गत आंकड़ों संबंधी मूल्य नीति तैयार करनी होती है।

2. उद्देश्य

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा अन्य सांख्यिकीय एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए साझा करने योग्य तथा साझा नहीं करने योग्य आंकड़ों को परिभाषित करने, इसके प्रसारण के लिए नियम तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करने तथा एनडीएसएपी 2012 में निर्धारित समग्र ढाँचे के भीतर इसके मूल्य निर्धारण के लिए सांख्यिकीय आंकड़ा प्रसारण संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य अधिकतम संभावित समुदाय को राष्ट्रीय सांख्यिकी उपलब्ध करवाना, तथा जहाँ उचित हो, प्रारूप के चयन सहित, सांख्यिकीय आंकड़ों तथा रिपोर्टों तक प्रयोगकर्ताओं की पहुँच को सुलभ बनाना है।

3. कार्यक्षेत्र

ये दिशा-निर्देश सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मिलान, संकलन और प्रत्यक्ष रूप से तैयार किए गए या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त किए गए सभी आंकड़ों पर लागू होते हैं।

4. आंकड़ा वर्गीकरण

सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश भर में विभिन्न प्रकार के वृहद स्तरीय सर्वेक्षणों के संचालन तथा उनके परिणामों के प्रकाशन के अलावा अनेक क्षेत्रों में नियमित आधार पर आंकड़ों का संग्रहण, संकलन तथा प्रसारण करता है। इस प्रकार के सभी आंकड़ों को निम्नलिखित प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:

क. साझा करने योग्य आंकड़ा: उन सभी आंकड़ा सेटों, जो यदि इन्हें सार्वजनिक किए जाएं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होता या जो किसी व्यक्तिगत सूचना प्रदानकर्ता तथा प्रतिष्ठान की पहचान नहीं रखते उनको साझा करने योग्य समझा गया है। साझा करने योग्य आंकड़ा सेटों को निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:

1) **श्रेणी क (खुली पहुँच आंकड़ा):** सम्मुचित/विक्षेपित सूचना तथा प्रकाशन जिसे प्रयोगकर्ताओं के साथ बिना लागत के साथ साझा किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित प्रकार के आंकड़े शामिल हैं:

- (i) राष्ट्रीय लेखा से संबंधित आंकड़े
- (ii) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)
- (iii) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) – का एनआईसी 2 अंकीय स्तर पर
- (iv) उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) वॉल्यूम-I
- (v) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्टें
- (vi) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) की रिपोर्टें

1) **श्रेणी ख (लागत रहित प्रतिबंधित पहुँचआंकड़ा):** एमओएसपीआई द्वारा सर्वेक्षणों/जनगणनाओं के माध्यम से एकत्र किया गया प्राथमिक इकाई स्तरीय आंकड़ा तथा व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों की पहचान संबंधी विवरण को छुपाने या गुमनाम करने के पश्चात द्वितीय स्रोतों से एकत्र किया गया मद स्तरीय आंकड़ा। इस प्रकार के आंकड़ों तक पंजीकरण के पश्चात पहुँच की जा सकती है। इसमें निम्नलिखित प्रकार के आंकड़े शामिल हैं:

- (i) आर्थिक गणना संबंधी इकाई स्तरीय आंकड़े
- (ii) इकाई स्तरीय एएसआई आंकड़े
- (iii) इकाई स्तरीय एनएसएस सर्वेक्षण आंकड़े
- (iv) मद स्तरीयआईआईपी आंकड़े
- (v) एएसआई वॉल्यूम-II
- (vi) अन्वेषक इकाइयों की कस्बा-वार पूर्ण सूचना सहित यूएफएस सार आंकड़ा, यूएफएस ब्लॉक की संख्या, परिवारों की संख्या, केवल उन क्षेत्रों जिनमें सैन्य/अर्ध-सैन्य प्राधिकारियों की विशिष्ट अनुमति के साथ यूएफएस किया गया है, को छोड़कर मेटाडाटा सहित क्षेत्र के प्रकार सहित शहरी फ्रेम सर्वेक्षण सार।

3. **श्रेणी ग (प्रतिबंधित आंकड़े जिसे देखने के लिए शुल्क देना होगा):** यूएफएस ब्लॉक के नक्शे पंजीकरण तथा निम्नलिखित शुल्क के भुगतान के पश्चात उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध होंगे:

- (i) एक किसी विशेष कस्बे में कुल यूएफएस ब्लॉक के 25% से कम ब्लॉकों के नक्शे 10 रु. प्रति यूएफएस ब्लॉक पर उपलब्ध करवाये जाएंगे बशर्ते कि उनका न्यूनतम मूल्य 500/- रु. हो। आकस्मिक प्रभार जैसे किफोटोकॉपी, स्टेशनरी, आदि भी उपयोगकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे। तथापि, उन क्षेत्रों के यूएफएस नक्शे, जिसके लिए यूएफएस का फील्ड कार्य संचालन सैन्य/अर्ध-सैन्य अधिकारियों आदि की विशेष अनुमति से संचालित किया गया था, उपलब्ध नहीं करवाये जाएंगे।
- (ii) प्रामाणिक गैर-वाणिज्यिक एजेंसियां, जिन्हें केवल सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए यूएफएस मानचित्रों की आवश्यकता होगी, को महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (डीजी, एनएसएसओ) के अनुमोदन से किसी एक विशेष कस्बे के कुल ब्लॉकों के 25% से अधिक के नक्शे प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।
- (iii) महानिदेशक, एनएसएसओ की अनुमति से सरकारी एजेंसियों को यूएफएस नक्शे निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।

ख. **गैर-साझा करने योग्य आंकड़े:** वे सभी डाटासेट जो कि साझा करने योग्य आंकड़ों के दायरे से बाहर हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) यूएफएस आंकड़े अथवा उन क्षेत्रों के नक्शे जिनके लिए यूएफएस फील्ड कार्य का संचालन केवल सैन्य/अर्ध-सैन्य प्राधिकारियों आदि की विशेष अनुमति से किया गया था।
- (ii) व्यक्तिगत सूचना प्रदाताओं/प्रतिष्ठानों के पहचान सम्बन्धी विवरणों को शामिल करने वाले डाटासेट। इस श्रेणी के कुछ उदाहरणों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), के इकाई स्तरीय आंकड़ों में सूचनाप्रदाताओं/अधिष्ठापनों का पहचान विवरण, एएसआई तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण; उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तैयार करने के लिए चुने गए विभिन्न ग्रामीण तथा शहरी बाजारों की दुकानों से एकत्रित किए गए आंकड़े और मूल्य शामिल हैं।
- (iii) व्यक्तिगत सूचनाप्रदाता की पहचान अथवा जानकारी प्रकट करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किए जाने वाले आंकड़े। उदाहरण के लिए, आसानी से पहचानी जाने वाली भौगोलिक इकाई में दो व्यक्तिगत सूचनाप्रदाताओं के आंकड़े साझा नहीं किए जाएंगे। साझा ना किए जाने वाले आंकड़ों में नकारात्मक सूची (एनडीएसएपी, 2012 के प्रावधानों में निर्दिष्ट) शामिल होगी।
- (iv) सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परिणाम/तकनीकी दस्तावेजों को तैयार करने के लिए आंकड़ा संवीक्षा तथा सारणियन आदि से संबंधित मध्यवर्ती वर्कशीट।
- (v) अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों या सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के स्रोतों से संग्रहित आंकड़ों का साझाकरण इस प्रकार के स्रोतों के लिए निर्धारित आंकड़ा साझाकरण प्रोटोकॉल के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

5. प्रसारण

साझा करने योग्य आंकड़ों का प्रसारण स्पष्टता, निष्पक्षता, लचीलापन, पारदर्शिता, वैध अनुरूपता, गुणवत्ता, सुरक्षा, जवाबदेही, आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतों के सेट द्वारा निर्देशित होगा तथा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 में निर्धारित सिद्धांतों की अवहेलना किए बिना कार्यान्वित किए जाएंगे। इसके अलावा, नागरिकों की आवश्यकताओं को केन्द्रित करते हुए आंकड़ों को सुगम, यूजर फ्रेंडली तथा समय पर प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाते हैं:

- (1) सभी साझा करने योग्य आंकड़े सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।
- (2) सभी साझा करने योग्य आंकड़े साफ तथा स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- (3) साझा करने योग्य आंकड़ों का मेटाडाटा मानक प्रारूप में उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
- (4) डाटा निष्पक्ष तथा वास्तविक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- (5) डाटा जारी करने का कैलेंडर सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
- (6) प्रसारण कार्यक्रम में परिवर्तनों, यदि कोई हो, की सार्वजनिक रूप से पहले से घोषणा की जानी चाहिए।
- (7) श्रेणी 'ख' के अंतर्गत साझा योग्य आंकड़ों की मांग अपर महानिदेशक, आंकड़ा भंडारण तथा प्रसारण प्रभाग, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ईस्ट ब्लॉक -10, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110066, फैक्स नंबर 011-26160053, ई-मेल: adg.dsdd@mospi.gov.in

को अनुलग्नक के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। श्रेणी 'ग' (यूएफएस नक्शों से संबंधी) के अंतर्गत साझा किए जाने वाले आंकड़ों की मांग एनएसएसओ के क्षेत्रीय कार्यालयों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- (8) श्रेणी 'ख' या 'ग' के अंतर्गत साझा योग्य आंकड़े उपयोगकर्ता को एक निर्धारित अनुरोध/भुगतान की प्राप्ति पर उचित समय में आसान तरीके से उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। प्रतिबंधित/भुगतान लेकर साझा करने योग्य आंकड़ों के किसी भी अनुरोध की स्वीकृति शीघ्र देने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।
- (9) मेटाडेटा सहित डाटा फ़ाइल प्रचलित प्रारूपों (.csv, .xlsx, आदि) में डाउनलोड करने के अनेक विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- (10) अंतिम आंकड़ों में बदलाव, जब अत्यधिक आवश्यक हो, को जहां तक संभव हो, सार्वजनिक रूप से शीघ्रातिशीघ्र प्रसारित किया जाना चाहिए।
- (11) संशोधित अंतिम आंकड़ों की उपलब्धता, संशोधन के उपयुक्त कारणों सहित, वेबसाइट पर शीघ्रातिशीघ्र संचारित की जानी चाहिए।
- (12) प्रसारण के लिए सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट के अलावा, जारी किए गए आंकड़े तथा रिपोर्ट के बारे में और अधिक जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए।

6. दिशा-निर्देशों की समीक्षा

भविष्य में सुधार के लिए उपयोगकर्ताओं को उनका फीडबैक देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ताओं के फीडबैक पर विचार करते हुए समय-समय इन दिशा-निर्देशों की पर समीक्षा की जा सकती है।

अनुलग्नक

प्रतिबंधित प्रवेश डेटा के लिए आवेदन

आवेदक की श्रेणी:	वैयक्तिक/संगठन
यदि आवेदक संगठन से है	
संगठन की श्रेणी	सरकारी मंत्रालय/विभाग सरकारी एजेंसी (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, इत्यादि) स्पष्ट करें _____ विश्वविद्यालय अनुसंधान केन्द्र निजी कम्पनी अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारतीय गैर-सरकारी संगठन गैर-भारतीय, गैर-सरकारी संगठन अन्य स्पष्ट करें _____
अनुरोधित डेटा के उपयोगकर्ताओं की	

अनुमानित संख्या	
आवेदक का नाम	उपाधि _____ पहला नाम मध्य नाम अंतिम नाम
पदनाम	
पत्राचार का पता	
टेलीफोन नंबर	
ईमेल	
वेबसाइट	
डेटा के उपयोग के उद्देश्य का विवरण	
डेटा अभिगम समझौता/सहमति <ol style="list-style-type: none"> 1. अनुरोधित डेटा तक पहुंच केवल आवेदक तक ही सीमित होगा तथा यदि किसी संगठन द्वारा आवेदन किया जाता है, तो उस संगठन के वास्तविक उपयोगकर्ता ही उसका उपयोग कर सकते हैं। 2. डेटा का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए होगा। डेटा का स्वामित्व अथवा वैधानिक प्रवर्तन हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। 3. किसी भी निजी व्यक्ति, परिवार, व्यवसाय, अधिष्ठापन आदि की पहचान दर्शायी नहीं जाएगी, यदि किसी भी प्रकार की पहचान का भूलवश प्रकटीकरण हो भी जाता है, तो उस पहचान को आगे किसी के भी समक्ष उजागर नहीं किया जाएगा तथा न ही उस व्यक्ति/संस्था की पहचान का किसी भी प्रकार से उपयोग किया जाएगा तथा ऐसे मामलों की पूरी जानकारी सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को दी जाएगी। 4. आवेदक, इकट्ठा किए गए डेटा के अनाधिकृत उपयोग से बचने के लिए सुरक्षा उपाय क्रियान्वित करेगा। 5. किसी पुस्तक, सामग्री, पेपर, शोध, रिपोर्ट, प्रकाशन आदि, के नाम पर आंकड़ा प्रगृहित करके उसका उपयोग करने वालों को, स्थापित मानदंडों/प्रथाओं का अनुसरण करते हुए, आंकड़ा स्रोत बताना होगा। 6. डेटा के उपयोग अथवा इस पर आधारित किसी भी प्रकार की व्याख्या के लिए सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उत्तरदायी नहीं होगा। 	

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2019

F. No. Y-18020/9/2017-IIIC/CAP.— Recognizing the requirement and potential of dissemination of data, Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI), Government of India announced a comprehensive National Policy on Dissemination of Statistical Data in May, 1999 to streamline the statistical data dissemination system. With the passage of time and technological advancements, the modes of data dissemination have undergone major transformation requiring a modification of the existing guidelines. Further, as per “National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP)” formulated by Ministry of Science & Technology, Government of India in March, 2012, Ministries/Departments are required to classify their different types of data sets in terms of ‘shareable data’ and ‘non-

shareable data', and come out with a pricing policy of the data under restricted access. Accordingly, modified Guidelines on Statistical Data Dissemination, as in the Schedule appended to this notification, are being notified to define shareable and non-shareable statistical data generated by MoSPI and other statistical agencies, specify the terms and conditions for their dissemination.

SCHEDULE

Guidelines for Statistical Data Dissemination (GSDD)

(in accordance with NDSAP, 2012)

1. Background

Official statistics are key inputs for decision making and policy interventions and become public assets for conducting research both in public and private spheres. A culture of data sharing and collaboration amongst producers of official statistics may not only lead to saving in resources by avoiding duplication and redundancy but has great potential for creating a wealth of new knowledge. Recognizing the requirement and potential of dissemination of data, Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI), Government of India announced a comprehensive National Policy on Dissemination of Statistical Data in May, 1999 to streamline the statistical data dissemination system. With the passage of time and technological advancements, the modes of data dissemination have undergone major transformation requiring a modification of the existing guidelines. Further, in March 2012, Ministry of Science & Technology, Government of India formulated the "National Data Sharing and Accessibility Policy (NDSAP)" with an objective to facilitate access to Government of India owned shareable data (along with its usage information) in machine readable form through a wide area network all over the country. In compliance, Open Government Data (OGD) Platform (www.data.gov.in), an integrated repository of datasets, documents, services, tools and applications of various Ministries / Departments, was launched in October 2012 for public use. As per NDSAP, Ministries/Departments are required to classify their different types of data sets generated both in geospatial and non-spatial form in terms of 'shareable data' and 'non-shareable data', and come out with a pricing policy of the data under restricted access.

2. Objective

In the above backdrop, the **Guidelines on Statistical Data Dissemination** are being laid down to define shareable and non-shareable statistical data generated by MoSPI and other statistical agencies, specify the terms and conditions for its dissemination and pricing within the overall framework laid down in NDSAP 2012. The objective of these guidelines is to make available national Statistics to the widest possible community, and where appropriate, with a choice of format, to facilitate users in getting access to statistical data and reports.

3. Scope

These guidelines apply to all data collated, compiled and produced by MoSPI either directly or received from various Ministries/Departments by MoSPI.

4. Data Classification

MoSPI collects, compiles and disseminates data on a number of sectors on a regular basis, besides conducting a variety of large scale surveys across the country and publishing their results. All such data may be categorized as under:

A. **Shareable data** : All data sets, which do not compromise national security, if made public, or those which do not contain identification particulars of individual informants as well as establishments, are considered shareable. The shareable datasets are further categorized as follows:

1) **Category A (open access data)**: Aggregated/analyzed information and publications which will be shared free of cost with users. This includes the following type of data:

- (i) Data relating to National Accounts
- (ii) Consumer Price Index (CPI)
- (iii) Index of Industrial Production (IIP) -at NIC 2 digit level
- (iv) Annual Survey of Industries (ASI) Volume I
- (v) Reports of Central Statistics Office
- (vi) Reports of National Sample Surveys (NSS).

- 2) **Category B (Restricted access data free of cost):** Primary unit level data collected by MoSPI through surveys / censuses, and item level data collected from secondary sources, after suppression or anonymisation of the identification details of individuals/ establishments. Such data can be accessed by registration. This includes the following type of data:
 - (i) Unit level data of Economic Census
 - (ii) Unit level ASI data
 - (iii) Unit level NSS survey data
 - (iv) Item level IIP data
 - (v) ASI Vol II
 - (vi) Urban Frame Survey (UFS) summary data with town-wise complete information of Investigator Units, UFS block numbers, number of households, area type along with metadata except for the areas for which field work of the UFS has been carried out only with the specific permission from military / para-military authorities etc.
- 3) **Category C (Restricted access data which is priced) :** The maps of UFS blocks would be provided to users after registration and on payment of charges as below:
 - (i) The maps for not more than 25% of total UFS blocks in a particular town would be provided at a price of Rs.10/- per UFS block, subject to a minimum price of Rs.500/-. Incidental charges such as for photocopying, stationery, etc. would also be borne by the user. However, the UFS maps of areas for which the field work of UFS was carried out only with the specific permission from military/para-military authorities etc., would not be provided.
 - (ii) Bonafide non-commercial agencies that require UFS maps only for survey purpose may be considered for being provided maps of more than 25% of total blocks in a particular town with approval of Director General, National Sample Survey Office (DG, NSSO).
 - (iii) UFS maps may be provided to Government agencies free of cost with approval of DG, NSSO.

B. Non-Shareable data: All datasets which are outside the purview of shareable data. These include the following:

- (i) The UFS data or maps of areas for which the field work of UFS was carried out only with the specific permission from military/para-military authorities etc.
- (ii) Data sets containing identification particulars of individual informants/ establishments. Some examples in this category are identification particulars of informants/establishments in unit level data of Index of Industrial production (IIP), ASI and NSS sample surveys; and data on prices collected from different shops of various rural and urban markets selected for preparation of Consumer Price Index (CPI)
- (iii) Any data which can be directly or indirectly used to reveal the identity or information of individual informant. To illustrate, data of two individual informants in an identifiable geographic unit would not be shareable. The non-shareable data will comprise of the Negative List (as specified under the provisions of NDSAP, 2012).
- (iv) Intermediate worksheets on data scrutiny & tabulation etc., for preparation of results / technical documents of the Ministry of Statistics & PI.
- (v) Sharing of data obtained from other sources or compiled by MoSPI based on such sources, will be regulated as per the data sharing protocol laid down by such sources.

5. Dissemination

Dissemination of shareable data will be guided by a set of internationally accepted principles of openness, equitableness, flexibility, transparency, legal conformity, quality, security, accountability, etc. and will be implemented without infringing the principles laid down in the Right to Information (RTI) Act, 2005. Further, keeping citizens' requirement as the focus, the following guidelines are laid down to ensure easy, user friendly and timely dissemination:

- (1) Access to all shareable data should be made available through the MoSPI's website.

- (2) All shareable data should be presented in a clear and understandable form.
- (3) Metadata of the shareable data should be made available in the standard format.
- (4) Data should be made available on an impartial and objective basis.
- (5) Calendar of release of data should be made available in advance on MoSPI's website.
- (6) Changes in dissemination schedule, if any, should be publicly announced in advance.
- (7) Requisition for the shareable data under Category 'B' should be made to the Additional Director General, Data Storage and Dissemination Division, MOSPI, East Block -10, R.K.Puram, New Delhi – 110066, Fax No. 011 26160053, email: adg.dsdd@mospi.gov.in as per Annex. Requisition for the shareable data under Category 'C' (relating to UFS maps) should be made to the respective Regional Office(s) of NSSO.
- (8) Shareable data under Category 'B' or 'C' should be provided to the user on request in a convenient mode in a reasonable time on receipt of stipulated request/ payment. A provision should be made for quick acknowledgement of any request for restricted/ priced data.
- (9) Multiple options for downloading the data file in popular formats (.csv, .xlsx, etc.) along with its metadata should be made available.
- (10) Revision in final data, when deemed absolute necessary, should be publicly announced as soon as materially possible.
- (11) Availability of revised final data along with specific reason for the revision should be expressly communicated in the website.
- (12) In addition to MOSPI website for dissemination, social media may be used for generating wider awareness about the released data or reports.

6. Review of the Guidelines

Users may be encouraged to provide their feedback for improvements in future. These guidelines may be reviewed periodically duly considering users feedback.

Annexure

Application for Restricted Access Data

Category of applicant:	Individual/Organization
If the application from an organization,	
category of organization	Government Ministry/ Department Government agency (PSU, Autonomous body, etc.) Specify _____ University Research Centre Private Company International organization Indian Non-governmental organization Non-Indian Non-governmental organization Others Specify _____
Estimated number of users of requested data	
Name of applicant	Title ____ First Name Middle Name Last Name
Designation	
Postal address	
Telephone No.	
Email	
Website	
Description of intended use of data	
<u>Data Access Agreement</u>	
1. Access to requested data will be limited to the applicant, and in case of application made on behalf of an organization, to the bonafide users in the organization.	

2. The data will be only for the stated purpose(s). Data will not be used for proprietary or law-enforcement purposes.
3. No attempt will be made to identify any individual person, family, business, enterprise, etc. If such a unique disclosure occurs inadvertently, the identification will not be revealed to anyone nor any use will be made of the identity of any person/ entity discovered, and full details in such cases will be reported to Ministry of Statistics & Programme Implementation (MoSPI).
4. The applicant will implement security measures to prevent unauthorized access to data acquired.
5. Any books, articles, papers, theses, reports, publications, etc. that employ data obtained under this request, will cite the data source in accordance with the established norms/ practices.
6. MoSPI bear no responsibility for use of the data or for any interpretation based on it.

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

\